Government to take steps for amendment of certain clauses of Christian divorce law; and

(b) if so, what are the details in this regard and what is Central Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI DINESH GOSWAMI): (a) Yes, Sir.

(b) The Kerala High Court in its order in C.M.P. No. 17247/88 in O.P. No. 5805 of 1988 Smt. Mary Sonia Zacharia Vs. Union of India has directed the Union of India to take a decision on the recommendations of the Law Commission made in its 90th Report on the amendment of section 10 of the Indian Divorce Act, 1869. The matter has been taken up with certain Christian Organisations. It will be possible for the Government to take a decision on the issue involved only after ascertaining the views of those organisations as the policy of the Government is to introduce amendment in the personal law relating to any minority community only when the community concerned agrees to the same.

देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाना

480. **श्री राम नरेश यादव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिसम्बर, 1989 से 1990 में अब तक की अवधि के दौरान देश की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा ऐसे कदमों का देश की वित्तीय स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) 1990 के वर्ष के दौरान अब तक कुल कितनी धनराशि का आयात तथा निर्यात किया गया है?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री): (क) वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने मौद्रिक विस्तार की दर और बजटीय घाटे के आकार में तेजी से कमी लाने के उद्देश्य से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मौद्रिक और राजकोषीय नीति के क्षेत्र में उपाय किए हैं। किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं:-

वर्ष 1990-91 के पूर्वार्ध के संबंध में ऋण नीति 12 अप्रैल, 1990 को घोषित की गई थी। इस नीति के अन्तर्गत, सांविधिक नकदी अनुपात को मांग और समय देयताओं के निवल की रूप में सितम्बर, 1990 से 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 38.5 प्रतिशत किया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में सरकार कठोर राजकोषीय अनुशासन लागू करके 1989-90 (सं०अ०) के 11,750 करोड़ रुपए के बजट घाटे की तुलना में इसे 7,206 करोड़ रुपए पर ही रखने के लिए वचनबद्ध है।

मितव्ययिता के अनेक उपाय शुरू किए गए हैं। इनमें, (क) विदेश स्थित अनेक कार्यालयों को बन्द करना और विदेश में विभिन्न कार्यालयों में तैनात स्टाफ में कटौती करना (ख) सभी सरकारी विभागों के कार्यकलापों की समीक्षा करना; (ग) विदेश यात्रा बजट में 25 प्रतिशत कटौती करना; (घ) सरकारी विभागों में ईंधन की खपत में पिछले वर्ष के आधार पर 20 प्रतिशत कटौती करना; और (ङ) 3500 रुपए और इससे अधिक मूल वेतन पाने वाले अधिकारियों के अतिरिक्त महंगाई भत्ते को रोक रखना शामिल है। सरकार ने वास्तविक बजटीय उतार-चढ़ाव की प्रत्येक चार महीने में समीक्षा करने और जनता तथा संसद् को उससे अवगत कराते रहने का भी निर्णय लिया है।

इन उपायों के प्रभावों के बारे में अभी कुछ बताना संभव नहीं है।

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान अनन्तिम आधार पर 27,681 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ जिससे पिछले वर्ष की तुलना में 36.5 प्रतिशत की वृद्धि का पता चलता है। इस वर्ष अनन्तिम आधार पर 35,412 करोड़ रुपये का आयात हुआ जिससे वर्ष 1988-89 की तुलना में 27.9 प्रतिशत की वृद्धि का पता चलता है। वर्ष 1990-91 के केवल पहले दो महीनों (अप्रैल और मई, 1990) के लिए ही आंकड़े उपलब्ध हैं। पहले दो महीनों के दौरान अनन्तिम आधार पर 5,108 करोड़ रुपए का निर्यात (वर्ष 1989-90 की इसी अवधि की तुलना में 25.8 प्रतिशत की वृद्धि) हुआ और 6,222 करोड़ रुपय का आयात (अनन्तिम) (वर्ष 1989-90 की इसी अवधि की तुलना में 24.4 प्रतिशत की वृद्धि) हुआ था।